



Neutral Citation No. - 2026:AHC:26376-DB

ए.एफ.आर.

सुरक्षित दिनांक 13.01.2026

निर्णय दिनांक 06.02.2026

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक अपील संख्या - 4445 वर्ष 2005

बालक राम एवं अन्यअपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यप्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता : अख्तर अली, चेतन चटर्जी, जी.के. सिंह, एन.सी. त्रिपाठी, पंकज त्यागी, ऋषिकेश त्रिपाठी, एस.के. सिंह, शकील अहमद आजमी, श्रीमती अर्चना त्यागी, श्रीमती नयन श्री, सुधांशु श्रीवास्तव, योगेश श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ,

माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय,

(माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय द्वारा सुनाया गया)

1. अपीलकर्ता संख्या 2 की ओर से अपील पर बहस करने के लिए उच्च न्यायालय लीगल सर्विस कमिटी द्वारा नियुक्त अधिवक्ता श्री चेतन चटर्जी (जिन्हें इस न्यायालय ने अपीलकर्ता संख्या 3 की ओर से अपील पर बहस करने के लिए न्यायमित्र भी नियुक्त किया है) और राज्य की ओर से पेश हुए अपर शासकीय अधिवक्ता-1 श्री जी. एन. कनौजिया की बातें सुनीं; साथ ही विचारण न्यायालय के अभिलेख और विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और आदेश को देखा।

2. यह आपराधिक अपील, अपर सत्र न्यायाधीश सहारनपुर द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 37/1992 से उत्पन्न सत्र विचारण संख्या 66/1995 (राज्य बनाम अनूप सिंह और अन्य) के रूप

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



में दर्ज दिनांक 24.09.2005 को दिए गए निर्णय और सज़ा के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई है जिसमें अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता अनूप सिंह को धारा 364 और 302/34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषी ठहराया था और उन्हें धारा 364 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत 10 साल की कठोर कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई थी, और धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई थी। जुर्माना न भरने की स्थिति में, उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी। अपीलकर्ताओं राम कुमार, विनोद और बालक राम को भी धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास तथा 10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। जुर्माना न भरने की स्थिति में, उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी।

3. इस अपील के लंबित रहने के दौरान दो अपीलकर्ताओं, यानी अपीलकर्ता संख्या 1, बालक राम और अपीलकर्ता संख्या 4, विनोद की मृत्यु हो गई और इस न्यायालय द्वारा क्रमशः दिनांक 11.01.2023 और 08.01.2026 को पारित आदेशों के अंतर्गत उनके संबंध में अपील समाप्त हो गई। अब केवल अपीलकर्ता संख्या 2 और 3, यानी क्रमशः अनूप सिंह और राम कुमार ही अपीलकर्ता के तौर पर बचे हैं।

4. संक्षेप में अभियोजन पक्ष की कहानी इस प्रकार है:-

दिनांक 07.02.1992 को सुबह 6:00 बजे, अनूप सिंह और राम कुमार ने सहारनपुर ज़िले के मंडी पुलिस स्टेशन इलाके के मोहल्ला महागढ़ में स्थित बलदेव सिंह के घर से चंद्रपाल उर्फ चंद्रप्रकाश को जान से मारने की नीयत से अगवा कर लिया और दिनांक 08.02.1992 को दोपहर 1:00 बजे, उन्होंने फरीदाबाद ज़िले के बल्लभगढ़ पुलिस स्टेशन इलाके में बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन के पास चंद्रपाल उर्फ चंद्रप्रकाश की हत्या कर दी। इस मुकदमे में सूचना देने वाले बलदेव सिंह हैं, जो मृतक के भाई हैं। उन्होंने दिनांक 12.02.1992 को पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना आख्या दर्ज कराई, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया और जांच की गई। मृतक चंद्रप्रकाश का शव बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन के पास मिला था।

5. इस मुकदमे की जांच के दौरान, शव की जांच (पंचायतनामा) और शव-विच्छेदन किया गया, और धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत गवाहों के बयान दर्ज किए गए। आरोपियों

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



को गिरफ्तार किया गया। जांच अधिकारी ने आरोपी अनूप सिंह, राम कुमार, विनोद और बालक राम के खिलाफ चार्ज-शीट दाखिल की और न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया। इसके बाद, मुकदमे को सत्र न्यायालय में भेज दिया गया। धाराओं 364 और 302/34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप तय किए गए। सभी आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का सामना करने का फैसला किया।

6. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के कुल 12 गवाहों से पूछताछ की गई। अभियोजन पक्ष के सबूतों में सामने आए दोषी ठहराने वाले तथ्यों को अपील करने वालों के सामने रखा गया, जब धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उनके बयान दर्ज किए जा रहे थे। अपील करने वालों ने इन दोषी ठहराने वाले तथ्यों से इनकार किया और दावा किया कि उन्हें इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है।

7. विवादित निर्णय के ज़रिए, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया। इसलिए, यह अपील की गई है।

8. अपीलकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री चेतन चटर्जी ने कहा कि:-

(i) अभियोजन साक्षी--1 और अभियोजन साक्षी--2 को पहले से ही पता था कि आरोपी अनूप सिंह और राम कुमार मृतक को अपने साथ ले गए थे, लेकिन गुमशुदगी की आख्या दिनांक 07.02.1992 को हुई घटना के 5 दिन बाद दिनांक 12.02.1992 को ही दर्ज कराई गई।

(ii) अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि पर्चा (प्रदर्श क-1) की सामग्री आरोपी अनूप सिंह की हस्तलिपि में है।

(iii) कोई भी सिर्फ 7,500 रुपये के लिए किसी की हत्या नहीं करेगा और नौकरी पाने के लिए मृतक द्वारा आरोपी अनूप सिंह और राम कुमार को दी गई कथित धनराशि के बारे में अभियोजन साक्षी--1 के बयान में विरोधाभास हैं। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष घटना के मकसद को साबित करने में विफल रहा है।

(iv) चिकित्सकीय साक्ष्य अभियोजन पक्ष की बात की पुष्टि नहीं करते हैं।

(v) अभियोजन पक्ष 'आखिरी बार साथ देखे जाने' के साक्ष्य को साबित करने में नाकाम रहा है। अगर यह साबित भी हो जाता, तो भी सिर्फ इसी के आधार पर सज़ा नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह बहुत कमज़ोर साक्ष्य है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(vi) इस मुकदमे में कोई चक्षुदर्शी साक्षी- नहीं है और यह मुकदमा परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित है। परिस्थितियों की कड़ी अधूरी है।

9. दूसरी ओर, विवादित निर्णय का समर्थन करते हुए, राज्य की ओर से पेश पर शासकीय अधिवक्ता-1 श्री जी. एन. कनौजिया ने कहा कि:-

(i) गुमशुदगी की आख्या दर्ज कराने में हुई विलंब के बारे में अभियोजन साक्षी-2 बलदेव सिंह ने स्पष्टीकरण दिया।

(ii) अभियोजन साक्षी-4 देश राज ने आरोपी अनूप सिंह द्वारा लिखे गए पर्चे को सही ढंग से साबित किया है।

(iii) घटना का मकसद वह पैसा है जो मृतक ने नौकरी पाने के लिए आरोपी को दिया था; यह बात अभियोजन साक्षी-1 जसमती ने साबित की है।

(iv) अभियोजन पक्ष ने 'आखिरी बार साथ देखे जाने' का साक्ष्य पेश किया है, जो हालात की उस कड़ी को पूरा करता है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आरोपी ने ही अपराध किया है।

10. पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा दी गई विरोधी के तर्कों पर विचार करने के बाद, सबसे पहले गवाहों की गवाही का विश्लेषण करना उचित होगा।

11. अभियोजन साक्षी-1 श्रीमती जसमती मृतक की पत्नी हैं। उन्होंने बताया कि वह आरोपी अनूप सिंह और राम कुमार को जानती थीं। वे उनके घर आए और उनके पति के बारे में पूछा, जो उस समय घर पर नहीं थे। उन्होंने उन्हें कागज़ की एक पर्ची दी और कहा कि अगले दिन चंद्रप्रकाश को रामपुर भेज दें। चंद्र प्रकाश (स्वर्गीय) अगले दिन रामपुर नहीं गए। उन्होंने बयान दिया कि अगली सुबह अनूप और राम कुमार फिर उनके घर आए और उनके पति को अपने साथ ले गए। उन्होंने आगे बताया कि उसके बाद उनके पति घर नहीं लौटे। उन्हें फ़ाइल से एक फ़ोटो दिखाई गई और उन्होंने पहचाना कि वह फ़ोटो उनके पति की थी। उन्होंने आगे कहा कि इस घटना से पहले, उनके पति ने नौकरी पाने के लिए आरोपी अनूप सिंह और राम कुमार को 7,500 रुपये दिए थे। उन्होंने आगे बताया कि वह अपने पति को घर पर दो आरोपियों, अनूप सिंह और राम कुमार के साथ छोड़कर शौच के लिए बाहर गई थीं। जब वह वापस लौटीं, तो उनके पति और दोनों आरोपी घर से जा चुके थे। उनके इलाके के लोग 2 या 3

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



दिन बाद पुलिस स्टेशन गए। वह खुद काफी देर बाद पुलिस स्टेशन गई। उन्होंने आगे कहा कि अगर जांच अधिकारी ने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उनके बयान में ₹0 7,500 की जगह सिर्फ ₹0 7,000 की धनराशि लिखी है, तो वह इसकी वजह नहीं बता सकती।

जिरह के दौरान, उन्होंने बताया कि आरोपी अनूप सिंह और राम कुमार उनके रिश्तेदार थे और उन्होंने उनके पति को नौकरी दिलाने के लिए उनसे 7,500 रुपये लिए थे। आरोपियों ने यह 7,500 रुपये की धनराशि उनके पति की हत्या से 2-3 महीने पहले ली थी। इस धनराशि के भुगतान के लिए कोई लिखित समझौता नहीं हुआ था।

12. अभियोजन साक्षी-2 बलदेव सिंह मृतक के भाई हैं। उन्होंने बल्लभगढ़ में चंद्रप्रकाश के कपड़ों की पहचान की थी, जिससे यह साबित हुआ कि बरामद शव मृतक चंद्रप्रकाश का ही था। उन्होंने बयान दिया कि लगभग 5 साल पहले, आरोपी अनूप सिंह और राम कुमार उनके घर आए और उनके भाई चंद्रप्रकाश (अब मृत) की पत्नी को एक चिट्ठी दी, जिसमें चंद्रप्रकाश को रामपुर बस स्टैंड भेजने के लिए कहा गया था। अगली सुबह दोनों आरोपी फिर से उनके घर आए और चंद्रप्रकाश को अपने साथ ले गए। उसके बाद उनका भाई कभी वापस नहीं लौटा। चंद्रप्रकाश (मृतक) आरोपी अनूप सिंह और राम कुमार के मामा थे। अनूप सिंह और राम कुमार सगे भाई हैं। उन्होंने आगे बताया कि दिनांक 12.02.1992 को, यानी घटना से 2-3 दिन पहले, वे अपने पड़ोसियों के साथ मंडी पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन संबंधित पुलिसकर्मियों ने प्रथम सूचना आख्या दर्ज करने से इनकार कर दिया था; हालांकि, बाद में उसी दिन आख्या दर्ज कर ली गई। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी द्वारा लिखा गया एक नोट (पर्चा) पुलिस को दिया गया था।

जिरह के दौरान उन्होंने कहा कि दारोगा ने कभी उनका बयान दर्ज नहीं किया था। अगर दारोगा ने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उनका बयान पहले ही दर्ज कर लिया होता, तो वे इसका कारण नहीं बता सकते।

13. अभियोजन साक्षी-3 कृष्ण लाल मृतक के पड़ोसी हैं। उन्होंने गवाही दी कि पाँच साल से भी ज़्यादा समय पहले, सुबह लगभग 8:30 बजे, अनूप सिंह, राम कुमार और चंद्रप्रकाश उर्फ चंद्रपाल (मृतक) रामपुर बस स्टैंड पर ऋषिपाल की दुकान के सामने उनसे मिले थे। उन्होंने कहा कि वे बोरे और जूट के थैले खरीदने दिल्ली जा रहे थे। उन्होंने आरोपी अनूप सिंह की लिखावट

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



और हस्ताक्षर को पहचाना। उन्हें पेपर संख्या 5/2 दिखाया गया और उसे देखकर उन्होंने बताया कि उस पर लिखी बातें न्यायालय में मौजूद आरोपी अनूप सिंह ने लिखी थीं।

जिरह के दौरान, उन्होंने बताया कि दारोगा जी ने उनका बयान पाँच महीने बाद दर्ज किया था। उन्होंने पुलिस को बताया था कि उन्होंने मृतक चंद्रपाल को दिनांक 06.02.1992 को रामपुर बस स्टैंड पर आरोपियों के साथ देखा था। उन्होंने आगे कहा कि अगर दारोगा जी ने उनके बयान में यह दर्ज किया है कि उन्होंने मृतक को आरोपियों के साथ दिनांक 07.02.1992 को देखा था, तो वे इस अंतर का कारण नहीं बता सकते।

14. अभियोजन साक्षी-4 देश राज ने बताया कि वह आरोपी अनूप सिंह और राम कुमार को जानता था। उसकी किराने की दुकान थी। लगभग 5 साल पहले, सुबह करीब 6:00 बजे, आरोपी अनूप सिंह और राम कुमार उसकी दुकान पर आए और उससे कागज़ का एक टुकड़ा और पेंसिल मांगी। अनूप सिंह ने उसकी दुकान पर बैठकर कागज़ पर कुछ लिखा था। उसने आगे बताया कि दारोगा ने पांच महीने बाद उसका बयान दर्ज किया था।

15. अभियोजन साक्षी-5 एम.एस.अहलावत वह डॉक्टर हैं जिन्होंने बताया था कि दिनांक 10.02.1992 को वे चंडीगढ़ के सिविल अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के तौर पर तैनात थे। उस दिन, उन्होंने एक अज्ञात शव का शव-विच्छेदन किया था और मौत से पहले लगी निम्नलिखित चोटें पाई थीं:-

“मृतक की दोनों आँखों और माथे पर काफी सूजन पाई गई। खोपड़ी की जाँच करने पर, क्रेनियल कैविटी (खोपड़ी के अंदर का हिस्सा) खून से भरी हुई मिली और क्रेनियल फोसा (खोपड़ी के अंदर के गड्ढे) के अंदरूनी और बीच वाले हिस्सों में फ्रैक्चर पाए गए, जो जमे हुए खून से भरे हुए थे। बाकी सभी अंग ठीक थे। मौत का कारण शरीर के ज़रूरी हिस्सों पर लगी चोटों की वजह से शॉक और हेमोरेज (अत्यधिक रक्तस्राव) है; ये चोटें मौत से पहले लगी थीं और मौत का कारण बनने के लिए काफी थीं। रेल दुर्घटना से चोट लगने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।”

उन्होंने शव-विच्छेदन आख्या को प्रमाणित किया है, जिसे प्रदर्श क-2 के रूप में पेश किया गया है।

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जिरह के दौरान, उन्होंने बताया कि उन्होंने शव-विच्छेदन आख्या में शव-विच्छेदन के समय का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस ने उन्हें जानकारी दी थी कि मृतक किसी नशीले पदार्थ के असर में था, जिसकी वजह से वह चलती ट्रेन से गिर गया और उसकी मौत हो गई। मृतक की मौत दिनांक 09.02.1992 को किसी भी समय हो सकती थी। मृतक के शरीर पर पाई गई चोटें चलती ट्रेन से गिरने के कारण आई हो सकती थीं।

16. अभियोजन साक्षी-6 उपपुलिस अधीक्षक बी.पी.सिंह ने बताया कि दिनांक 19.09.1992 को वे मंडी पुलिस स्टेशन में प्रभारी निरीक्षक के तौर पर तैनात थे। उस दिन उन्होंने इस मुकदमे की जांच शुरू की। उसी दिन उन्होंने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत गवाहों के बयान दर्ज किए। उसी दिन, अभियोजन साक्षी-1 जसमती ने उन्हें आरोपी अनूप सिंह का लिखा एक नोट दिया, जो प्रदर्श क-1 है। उन्होंने फर्द प्रदर्श क-3 तैयार किया। दिनांक 20.02.1992 को, उन्होंने शाम लगभग 05:20 बजे दिल्ली बस स्टैंड से आरोपी अनूप सिंह को गिरफ्तार किया और दिनांक 23.02.1992 को सुबह लगभग 5:50 बजे बेहट बस स्टैंड से आरोपी बालक राम और विनोद कुमार को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की। इस मुकदमे की जांच दिनांक 24.03.1992 तक उनके पास रही।

17. अभियोजन साक्षी-7 सत्यबीर एक मोची हैं जो मृतक को जानते थे। उन्होंने बताया कि लगभग 6 साल पहले शाम 6:00 बजे, जब वे सहारनपुर जाने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचे, तो उन्होंने मृतक और आरोपी व्यक्तियों को वहाँ देखा। उनके साथ आरोपी अनूप सिंह, राम कुमार, बालक राम और विनोद भी थे। इसके बाद, वे उनसे मिले और साथ में चाय पी। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने उनसे बोरे खरीदने के लिए बल्लभगढ़ जाने को कहा।

18. अभियोजन साक्षी-8 प्रभारी निरीक्षक एस.पी.सिंह ने बताया है कि दिनांक 08.07.1992 को उन्होंने जांच अपने हाथ में ली और आरोपी राम कुमार को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की। उन्होंने संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को धारा 82 और 83 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक आख्या भेजी थी।

19., अभियोजन साक्षी-9 सहायक उपनिरीक्षक बाबू लाल पुलिस स्टेशन बल्लभगढ़ सिटी, जिला फरीदाबाद ने बताया कि दिनांक 09.02.1992 को दोपहर लगभग 12:00 बजे, वह अपनी पुलिस टीम के साथ एल्सन कॉटन मिल के सामने खड़े थे, तभी छुट्टन जाट के बेटे रिछपाल ने

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उन्हें जुबानी तौर पर बताया कि रेलवे लाइन के पास गेहूँ के खेत में एक युवक की लाश पड़ी है। मौके पर पहुँचने पर उन्होंने देखा कि शव रेलवे लाइन की सीमा से लगभग चार कदम दूर था। उन्होंने शव की जाँच (पंचायतनामा) की और शव को शव-विच्छेदन के लिए भेजा। उन्होंने पंचायतनामा आख्या को साबित किया, जिसे प्रदर्श क-4 के तौर पर पेश किया गया था।

20. अभियोजन साक्षी-10 कॉन्स्टेबल ऋषिपाल सिंह, पुलिस स्टेशन बेहट, ज़िला सहारनपुर ने बताया कि वे पुलिस स्टेशन मंडी में कॉन्स्टेबल के तौर पर तैनात थे। दिनांक 12.02.1992 को सुबह 10:30 बजे बलदेव सिंह ने अपने भाई चंद्रप्रकाश के लापता होने के बारे में पुलिस स्टेशन में लिखित आख्या दी थी, जिसे उन्होंने जनरल डायरी में रपट संख्या 23 के तौर पर दर्ज किया था। मूल जनरल डायरी नष्ट हो चुकी है और उसकी छायाप्रति, जो उनकी अपनी लिखावट में है, फाइल में मौजूद है; इसे प्रदर्श क-10 के तौर पर दिखाया गया है।

फरीदाबाद से लौटने पर दिनांक 19.01.1992 को इस मुकदमे की जांच एस0पी0 सिंह को सौंपी गई और इसे गुमशुदगी की आख्या से बदलकर धाराओं 364, 302/201 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 37/1992 में बदल दिया गया।

21. अभियोजन साक्षी-11 राम बाबू, जो इस मुकदमे के तीसरे जांच अधिकारी थे, ने बताया कि उन्होंने आरोपपत्र दाखिल कर दी है।

22. अभियोजन साक्षी-12 हरपाल सिंह, उपमहानिरीक्षक नैनीताल (उत्तरांचल) के उपनिरीक्षक/रीडर हैं। उन्होंने जांच के दौरान अभियोजन साक्षी-11 राम बाबू की मदद की थी और घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श क-15) तैयार किया था।

23. आगे बढ़ने से पहले, यह ध्यान में रखते हुए कि हम एक ऐसे मुकदमे पर विचार कर रहे हैं जिसका निर्णय परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर किया जाना है, उन कानूनी सिद्धांतों पर ध्यान देना उपयोगी होगा जिन्हें ऐसे आपराधिक मुकदमे में ध्यान में रखा जाना चाहिए। जब साक्ष्य परिस्थितिजन्य हों, तो जिन परिस्थितियों के आधार पर दोषी होने का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें सबसे पहले पूरी तरह से साबित किया जाना चाहिए; और इस तरह साबित हुए सभी तथ्य केवल आरोपी के दोषी होने की संभावना के अनुरूप ही होने चाहिए। इसके अलावा, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए कि जिस बात को साबित करना है, उसके अलावा बाकी सभी संभावनाओं को खारिज कर

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



दें। दूसरे शब्दों में, हालात की ऐसी कड़ी होनी चाहिए जो इतनी पूरी हो कि आरोपी के बेगुनाह होने का कोई वाजिब आधार न बचे, और यह ऐसी होनी चाहिए जिससे यह पता चले कि पूरी इंसानी संभावना के अनुसार यह काम आरोपी ने ही किया होगा।(देखें **हनुमत गोविंद नरगुंडकर और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, AIR 1952 SC 343; शरद बिरधीचंद सारडा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 SCC 116**)। **विजय शंकर बनाम हरियाणा राज्य, (2015) 12 SCC 644** मुकदमे में, उच्चतम न्यायालय ने **शरद बिरधीचंद सारडा (उपर्युक्त) और बबलू बनाम राजस्थान राज्य, (2006) 13 SCC 116** में दिए गए अपने पहले के फैसलों का पालन करते हुए, परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित एक मुकदमे के संबंध में यह कहा कि "सामान्य सिद्धांत यह है कि परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित मुकदमे में, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें ठोस और मजबूती से स्थापित किया जाना चाहिए; ये परिस्थितियां ऐसी निश्चित दिशा वाली होनी चाहिए जो बिना किसी संदेह के आरोपी के अपराध की ओर इशारा करती हों; सभी परिस्थितियों को मिलाकर एक ऐसी पूरी कड़ी बननी चाहिए जिससे इस निष्कर्ष से बचने का कोई रास्ता न हो कि पूरी मानवीय संभावना के अनुसार अपराध आरोपी ने ही किया था, और वे परिस्थितियां आरोपी के अपराध के अलावा किसी अन्य संभावना या परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होनी चाहिए और आरोपी की बेगुनाही के साथ मेल नहीं खानी चाहिए"। इसके अलावा, **(शरद बिरधीचंद सारडा मुकदमे के मशहूर निर्णय के प्रस्तर 153 के अनुसार)** जिन हालात के आधार पर दोषी होने का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूरी तरह से साबित होने चाहिए; यानी उन्हें 'साबित होना ही चाहिए', न कि वे 'शायद साबित हों' वाली स्थिति में हों। इसके अलावा, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आपराधिक न्यायशास्त्र का सबसे बुनियादी सिद्धांत यह है कि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने से पहले न्यायालय के लिए यह पक्का होना ज़रूरी है कि वह दोषी है, न कि सिर्फ यह कि वह दोषी हो सकता है*; और 'हो सकता है' तथा 'ज़रूर है' के बीच का फ़ासला बहुत बड़ा होता है, जो अस्पष्ट अनुमानों को पक्के नतीजों से अलग करता है **(देखें शिवाजी सहराव बोबाडे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1973) 2 SCC 793)**। उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने **'देवी लाल बनाम राजस्थान राज्य' (2019) 19 SCC 447** मुकदमे में इन स्थापित कानूनी सिद्धांतों को फिर से दोहराया है। इस निर्णय के प्रस्तर 18 और 19 में यह कहा गया है कि:-

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



“18. इस मुकदमे के सभी तथ्यों का विश्लेषण करने और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए और उच्च न्यायालय के निर्णय में बताए गए हालात से जुड़े सबूतों की कड़ी पर विचार करने के बाद, यह साफ है कि आरोप साबित करने के लिए ये साक्ष्य अधूरे और बेमेल हैं, और इनके आधार पर बिना किसी शक के अपीलकर्ताओं को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हालाँकि अभिलेख पर मौजूद सामग्री से उन पर कुछ शक पैदा होता है, लेकिन अभियोजन पक्ष अपने मुकदमे को "शायद सच हो" के स्तर से ऊपर उठाकर "सच होना ही चाहिए" के स्तर तक ले जाने में नाकाम रहा है, जो आपराधिक आरोप में दोषी ठहराने के लिए कानूनन ज़रूरी है। यह कहना आम बात है कि आपराधिक मुकदमे में शक, चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, साक्ष्य की जगह नहीं ले सकता।

19. इसके अलावा, परिस्थितिजन्य सबूतों के मुकदमे में, अभिलेख पर मौजूद तथ्यों के आधार पर दो तरह की राय बन सकती है: एक जो आरोपी के दोषी होने की ओर इशारा करती है और दूसरी जो उसके निर्दोष होने की ओर। आरोपी निश्चित रूप से उस राय का लाभ पाने का हकदार है जो उसके पक्ष में हो। परिस्थितिजन्य सबूतों की गुणवत्ता और सामग्री को तय करने वाले सभी कानूनी मानदंडों के आधार पर आरोपी का अपराध साबित होना चाहिए; हमें यह कहने में कोई कठिनाई नहीं है कि इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष इन मानदंडों को पूरा करने में विफल रहा है।”

24. अभियोजन पक्ष के सबूतों और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर आपराधिक मुकदमे का निर्णय करने के कानूनी सिद्धांतों पर गौर करने के बाद, हम पाते हैं कि इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष आरोपी अपीलकर्ता का अपराध साबित करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों को सामने लाना चाहता है:-

(i) दिनांक 06.02.1992 को सुबह लगभग 6:00 बजे आरोपी अनूप सिंह और राम कुमार, अभियोजन साक्षी-4 देश राज की दुकान पर गए और उनसे कागज़ का एक टुकड़ा और पेंसिल मांगी। आरोपी अनूप सिंह ने कागज़ पर कुछ लिखा, (ii) उन्होंने दिनांक 06.02.1992 को अभियोजन साक्षी-1 श्रीमती जसमाती को एक पर्ची दी और उनसे कहा कि वे चंद्रप्रकाश (मृतक) को रामपुर भेज दें; और अगली सुबह वे फिर उनके घर गए और उनके पति को अपने साथ ले गए, (iii) दिनांक 07.02.1992 को सुबह लगभग 8:30 बजे, आरोपी अनूप सिंह, राम कुमार

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



और चंद्रप्रकाश (मृतक) रामपुर बस स्टैंड पर अभियोजन साक्षी-3 कृष्ण लाल से मिले, (iv) दिनांक 07.02.1992 को शाम लगभग 6:00 बजे, अभियोजन साक्षी-7 सत्यबीर ने मृतक और सभी आरोपियों को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखा, (v) दिनांक 09.02.1992 को दोपहर लगभग 12:00 बजे, फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ शहर में रेलवे लाइन के पास मृतक का शव मिला। (vi) मृतक की मौत का कारण मरने से पहले लगी चोटें थीं और (vii) इस घटना के पीछे का मकसद 7,500 रुपये थे, जो मृतक ने नौकरी दिलाने के लिए आरोपी अनूप सिंह और राम कुमार को दिए थे।

25. अब, हम इस बात की जाँच करेंगे कि क्या अभियोजन पक्ष ऊपर बताई गई सभी परिस्थितियों को सफलतापूर्वक साबित कर पाया है।

(i) अभियोजन पक्ष उस पर्ची पर निर्भर है जो कथित तौर पर आरोपी ने लिखी थी; अभिलेख के अनुसार, यह पर्ची पेन से लिखी गई थी, न कि पेंसिल से। लिखावट के बारे में कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है, इसलिए यह बात संदिग्ध है और इसे आरोपी के खिलाफ कोई मजबूत साक्ष्य नहीं माना जा सकता, (ii) मृतक का आरोपी-अपीलकर्ताओं के साथ घर से निकलना विवादित नहीं है, लेकिन यह उनकी अपनी मर्जी से हुआ था। आरोपी की पत्नी ने दिनांक 12.02.1992 से पहले किसी शक या धमकी के बारे में पुलिस से कोई शिकायत नहीं की थी। बिना किसी आपत्ति के साथ जाना, अपने आप में कोई दोषी ठहराने वाला साक्ष्य नहीं माना जा सकता, (iii) किसी सार्वजनिक जगह पर मौजूद होना, जहाँ बहुत से लोग आते-जाते हैं, कोई शक पैदा नहीं करता। उस जगह पर किसी झगड़े, धमकी या अजीब व्यवहार का कोई अभिलेख नहीं है, (iv) इस मुकदमे में आखिरी बार साथ देखे जाने का सिद्धांत कमजोर साक्ष्य है। मृतक को आखिरी बार दिनांक 7.02.1992 को शाम करीब 6:00 बजे आरोपी के साथ देखा गया था, लेकिन शव दिनांक 9.02.1992 को दोपहर के आसपास मिला। कई घंटों का लंबा अंतर 'आखिरी बार साथ देखे जाने' वाले साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाता है क्योंकि किसी और व्यक्ति के शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, (v) शव रेलवे लाइन के पास मिला था, लेकिन इससे आरोपी-अपीलकर्ताओं और शव मिलने की जगह के बीच कोई सीधा संबंध नहीं दिखता, (vi) नौकरी दिलाने के लिए 7,500 रुपये लेने का कथित मकसद संदिग्ध है क्योंकि वे दोनों मजदूर थे। इसके अलावा, मृतक की पत्नी ने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अपने बयान में धनराशि 7,000 रुपये बताई थी, जो अभियोजन पक्ष के मुकदमे के विपरीत है और (vii) अभियोजन साक्षी-5 डॉ. एम. एस. अहलावत, जिन्होंने शव-विच्छेदन किया था, ने कहा कि मृतक की मौत दिनांक 09.02.1992 को किसी भी समय चलती ट्रेन से गिरने से हो सकती थी; यह एक दुर्घटना हो सकती है क्योंकि इसका आरोपियों से कोई संबंध नहीं दिखता।

ऊपर बताए गए बयानों को ध्यान में रखते हुए, अहम सवाल यह है कि क्या पूरी तरह से परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित मुकदमे में, अपील करने वालों को दोषी ठहराने के लिए 'आखिरी बार साथ देखे जाने' का साक्ष्य काफी है?

26. आरोपी-अपीलकर्ताओं को दिनांक 07.02.1992 को शाम लगभग 6:00 बजे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मृतक के साथ आखिरी बार देखा गया था और दिनांक 09.02.1992 को दोपहर लगभग 12:00 बजे, फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ शहर में रेलवे लाइन के पास मृतक का शव मिला। शव का शव-विच्छेदन दिनांक 10.02.1992 को किया गया और डॉक्टर ने राय दी कि मृतक की मौत दिनांक 09.02.1992 को किसी भी समय हो सकती थी। इस मुकदमे पर विस्तार से बात करने से पहले, हम यह देख सकते हैं कि आम तौर पर, सिर्फ इस बात के आधार पर कि मरने वाले व्यक्ति को आखिरी बार आरोपी के साथ ज़िंदा देखा गया था, सज़ा सुनाना काफी नहीं हो सकता है (देखें: निज़ाम बनाम राजस्थान राज्य, (2016) 1 SCC 550; नवनीतकृष्णन बनाम राज्य, (2018) 16 SCC 161; और कन्हैया लाल बनाम राजस्थान राज्य, (2014) 4 SCC 715)। लेकिन, यह उन हालात की कड़ी में एक अहम कड़ी है जो कुछ हद तक पक्के तौर पर आरोपी के दोषी होने की ओर इशारा कर सकती है। 'आखिरी बार देखे जाने का सिद्धांत' तब लागू होती है जब आरोपी और मृतक को आखिरी बार ज़िंदा देखे जाने और मृतक के मृत पाए जाने के बीच का समय इतना कम हो कि आरोपी के अलावा किसी और व्यक्ति के अपराध करने की संभावना ही न रहे। कुछ मुकदमों में यह पक्के तौर पर साबित करना मुश्किल हो सकता है कि मरने वाले को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था, खासकर तब जब बीच में लंबा समय बीत गया हो और किसी और व्यक्ति के बीच में आने की संभावना हो (देखें: उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सतीश, (2005) 3 SCC 114)। ऐसा ही नज़रिया 'रामरेड्डी राजेश खन्ना रेड्डी और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य' (2006) 10 SCC 172 के मुकदमे में भी अपनाया गया था। इस मुकदमे में, 'उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सतीश' (उपर्युक्त)

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



और 'बोधराज बनाम जम्मू कश्मीर राज्य' (2002) 8 SCC 45 के फैसलों का पालन करते हुए, निर्णय के प्रस्तर 27 में यह कहा गया था कि " 'आखिरी बार साथ देखे जाने का सिद्धांत' तब लागू होती है जब आरोपी और मरने वाले को आखिरी बार ज़िंदा देखे जाने और मरने वाले के मृत पाए जाने के बीच का समय इतना कम हो कि आरोपी के अलावा किसी और व्यक्ति के अपराध करने की संभावना ही न रहे। ऐसे मुकदमों में भी न्यायालयों को कुछ पुष्टि करने वाले साक्ष्य देखने चाहिए।"

27. **रामवृक्ष बनाम छत्तीसगढ़ राज्य** (2016) 12 SCC 251 मुकदमे में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 'आखिरी बार देखे जाने का सिद्धांत' तभी लागू होती है जब आखिरी बार देखे जाने और मौत का पता चलने के बीच का समय इतना कम हो कि कोई और व्यक्ति अपराध नहीं कर सकता था। फिर भी, केवल यह परिस्थिति ही काफी नहीं है; अभियोजन पक्ष को ऐसी परिस्थितियों की पूरी कड़ी साबित करनी होगी जो आरोपी के अपराध को सिद्ध करे। इस निर्णय में, न्यायालय ने निम्नलिखित बातें कहीं:

"12. यह स्थापित कानून है कि किसी आरोपी को सिर्फ इस आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि उसे मृतक के साथ आखिरी बार देखा गया था। दूसरे शब्दों में, सिर्फ 'साथ देखे जाने' की परिस्थिति के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। आम तौर पर, 'आखिरी बार साथ देखे जाने का सिद्धांत' तब लागू होती है जब आरोपी और मृतक के आखिरी बार जीवित देखे जाने और मृतक के मृत पाए जाने के बीच का समय इतना कम हो कि आरोपी के अलावा किसी और व्यक्ति के अपराध करने की संभावना ही न रहे। दोषसिद्धि के लिए, सिर्फ 'साथ देखा जाना' ही काफी नहीं है; अभियोजन पक्ष को आरोपी का अपराध साबित करने के लिए परिस्थितियों की पूरी कड़ी जोड़नी होगी।"

28. इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **कृष्णन उर्फ रामासामी बनाम तमिलनाडु राज्य** (2014) 12 SCC 279 के मुकदमे में, **अर्जुन मारिक बनाम बिहार राज्य** 1994 Supp (2) SCC 372 में दिए गए अपने निर्णय का हवाला देते हुए यह बात कही:

"21. सिर्फ इस आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि मृतक के साथ आखिरी बार साथ देखा गया था। **अर्जुन मारिक बनाम बिहार राज्य** [1994 Supp (2) SCC 372: 1994 SCC (Cri) 1551] मुकदमे में इस न्यायालय ने (SCC पेज 385, प्रस्तर 31) यह कहा था:

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"31. इस तरह, यह साक्ष्य कि अपील करने वाला दिनांक 19-7-1985 की शाम को सीताराम के पास गया था और रात में मृतक सीताराम के घर पर रुका था, बहुत कमजोर और निर्णायक नहीं है। भले ही यह मान लिया जाए कि वे वहाँ थे, तो भी यह ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का साक्ष्य होगा कि अपील करने वाले को आखिरी बार मृतक के साथ देखा गया था। लेकिन यह स्थापित कानून है कि सिर्फ 'आखिरी बार साथ देखे जाने' की स्थिति से घटनाओं की वह कड़ी पूरी नहीं होती जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि यह केवल आरोपी के दोषी होने की संभावना से मेल खाती है; इसलिए, केवल इसी आधार पर सज़ा नहीं सुनाई जा सकती।"

29. मुकदमे के तथ्यों और परिस्थितियों और ऊपर बताए गए माननीय उच्चतम न्यायालय के कानून को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि चूंकि मृतक को आखिरी बार दिनांक 07.02.1992 को शाम लगभग 06:00 बजे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरोपी व्यक्तियों के साथ देखा गया था और दिनांक 09.02.1992 को दोपहर लगभग 12:00 बजे, मृतक का शव फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ शहर में रेलवे लाइन के पास मिला था और अभियोजन साक्षी-5 डॉ. एम.एस.अहलावत ने राय दी है कि मृतक की मौत दिनांक 09.02.1992 को हुई हो सकती है। इसलिए, इस मुकदमे में 'आखिरी बार साथ देखे जाने के सिद्धान्त' कानूनी रूप से मान्य नहीं है, क्योंकि कानून के अनुसार आखिरी बार देखे जाने और मौत के समय और जगह के बीच बहुत कम अंतर होना चाहिए। इस मुकदमे में समय का काफी अंतर है, जो इतना कम नहीं है कि किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की संभावना को खारिज किया जा सके। इसलिए, अभियोजन पक्ष अपने मुकदमे को बिना किसी उचित संदेह के साबित करने में विफल रहा है। नतीजतन, आरोपी-अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। फलस्वरूप, अपील स्वीकार किए जाने योग्य है और इसे तदनुसार स्वीकार किया जाता है। विचारण न्यायालय का निर्णय रद्द किया जाता है। अपीलकर्ता संख्या 2 और 3, यानी अनूप सिंह और राम कुमार, को उन सभी आरोपों से बरी किया जाता है जिनके लिए उन पर मुकदमा चलाया गया था।

30. अपीलकर्ता जेल में हैं। उनके ज़मानत बन्धपत्र रद्द कर दिए गए हैं और प्रतिभूओं को उन्मोचित कर दिया गया है।

31. अपीलकर्ता संख्या 2, अनूप सिंह और अपील करने वाले संख्या 3, राम कुमार की आपराधिक अपील स्वीकार की जाती है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



32. निर्णय और आदेश की एक प्रति, विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ, क्रियान्वयन के लिए संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/विचारण न्यायालय को भेजी जाए।

33. अधिवक्ता श्री चेतन चटर्जी इस अपील पर बहस करने के लिए 'न्याय मित्र' के तौर पर पेश होने के लिए अपनी 15,000 रुपये की व्यवसायिक शुल्क पाने के हकदार हैं।

(जय कृष्ण उपाध्याय, न्यायमूर्ति) (सिद्धार्थ, न्यायमूर्ति)

6 फ़रवरी, 2026

एकेटी

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"